अनुबोधन, खण्ड 1, अंक 3, सितम्बर 2025, पृष्ठ 86–104
ISSN: 3049-4184 (प्रिन्ट), 3108-1185 (ऑनलाइन)
प्रकाशित: **30 सितम्बर 2025**
जर्नल वेबसाइट: **https://anubodhan.org**

ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का प्रभाव

डॉ॰ अरूण प्रताप सिंह*

सारांश

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भारत सरकार की एक व्यापक और बहुआयामी पहल है जिसका उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना है। ग्रामीण भारत, जहाँ लगभग दो-तिहाई जनसंख्या निवास करती है, इस परिवर्तन की वास्तविक कसौटी है। ग्रामीण क्षेत्रों में लम्बे समय से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार और शासन सम्बन्धी सेवाओं की कमी रही है, जिसके कारण सामाजिक और आर्थिक विकास असमान बना रहा। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने इन्हीं खाइयों को पाटने का प्रयास किया है

डिजिटल इंडिया का दृष्टिकोण तीन मुख्य आधारों पर टिका है:

1. ***डिजिटल अवसंरचना का विकास:*** *जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर तक ब्रॉडबैंड नेटवर्क, सार्वजनिक वाई-फाई और मोबाइल कनेक्टिविटी का विस्तार शामिल है।*
2. ***डिजिटल सेवाओं का सार्वभौमिक वितरण:*** *जिससे नागरिकों को सरकारी योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और वित्तीय सेवाओं तक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पारदर्शी और त्वरित पहुँच मिल सके।*
3. ***डिजिटल सशक्तिकरण:*** *जिसके तहत डिजिटल साक्षरता, स्थानीय भाषा में सामग्री, और नागरिक सहभागिता को बढ़ावा दिया जाता है।*

ग्रामीण क्षेत्रों पर इसका प्रभाव कई स्तरों पर दिखाई देता है। शिक्षा में ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म और स्मार्ट कक्षाओं ने नई संभावनाएँ खोली हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में टेलीमेडिसिन और ई-हॉस्पिटल ने दूरस्थ गाँवों को विशेषज्ञ परामर्श और उपचार से जोड़ा है। कृषि क्षेत्र में ई-नाम (National Agriculture Market) और मोबाइल

*सहायक आचार्य, भूगोल विभाग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय महाविद्यालय, फाफामऊ, प्रयागराज

आधारित मौसम व बाजार सूचनाओं ने किसानों को बेहतर मूल्य और उत्पादन योजना की सुविधा दी है। साथ ही आधार आधारित बैंकिंग, यूपीआई और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) ने वित्तीय समावेशन को गति दी है, जिससे पारदर्शिता और भ्रष्टाचार में कमी आई है।

हालाँकि इन उपलब्धियों के साथ चुनौतियाँ भी बनी हुई हैं। कई दूरदराज़ इलाकों में अब भी स्थायी बिजली और हाई-स्पीड इंटरनेट का अभाव है। डिजिटल साक्षरता विशेषकर महिलाओं, बुजुर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में सीमित है। साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता जैसे मुद्दों पर पर्याप्त जागरूकता नहीं है, जिसके कारण ग्रामीण उपयोगकर्ता धोखाधड़ी और डेटा चोरी के प्रति संवेदनशील बने हुए हैं। इस शोध पत्र में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के ग्रामीण क्षेत्रों पर बहुआयामी प्रभाव का गहन अध्ययन किया गया है। विश्लेषण से स्पष्ट है कि डिजिटल इंडिया ने ग्रामीण भारत में शासन की पारदर्शिता, सेवा वितरण की गति, और नागरिकों के अवसरों में उल्लेखनीय सुधार किया है। फिर भी कार्यक्रम की स्थिर सफलता के लिए निरंतर निवेश, स्थानीय भाषाओं में डिजिटल सामग्री का विकास, साइबर सुरक्षा ढाँचे की मजबूती, और सामुदायिक भागीदारी अत्यावश्यक है।

डिजिटल इंडिया केवल तकनीकी परियोजना नहीं बल्कि ग्रामीण भारत के सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने को पुनर्गठित करने की प्रक्रिया है। यह न केवल सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक पहुँचा रहा है बल्कि ग्रामीण समाज को ज्ञान आधारित और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर कर रहा है। यह कार्यक्रम ग्रामीण भारत के लिए अवसरों का नया द्वार है। यदि सरकार निजी क्षेत्र और समाज मिलकर मौजूदा चुनौतियों का समाधान करें, तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भारत को आत्मनिर्भर बनाने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है।

मुख्य शब्द: *डिजिटल, ई-गवर्नेंस*

परिचय

भारत एक विशाल और विविधता से भरा देश है, जिसकी लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। कृषि, हस्तशिल्प और छोटे-मोटे उद्योग यहाँ की प्रमुख आजीविका हैं। स्वतंत्रता के बाद से कई योजनाएँ चलाई गईं, पंचवर्षीय योजनाओं से लेकर ग्राम पंचायतों के

विकेंद्रीकरण तक, फिर भी शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और बाजार की पहुँच में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच गहरा अंतर बना रहा। यह अंतर केवल आय और अवसरों तक सीमित नहीं था; सूचना और संचार की कमी ने इसे और गहरा किया।

बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का तेजी से विकास हुआ। इंटरनेट, मोबाइल फोन और उपग्रह संचार ने विश्व अर्थव्यवस्था को एक नया रूप दिया। लेकिन भारत के गाँव लंबे समय तक इनसे वंचित रहे। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट का प्रसार 10 प्रतिशत से भी कम था। इस "डिजिटल डिवाइड" ने शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक अवसरों में असमानता को और बढ़ाया।

इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए 1 जुलाई 2015 को भारत सरकार ने "डिजिटल इंडिया कार्यक्रम" की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित यह कार्यक्रम केवल तकनीकी परियोजना नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विकास का एक समग्र दृष्टिकोण है। इसका लक्ष्य है:

1. डिजिटल अवसंरचना को नागरिक अधिकार बनाना – यानी उच्च गुणवत्ता का इंटरनेट, सुरक्षित डिजिटल पहचान (आधार), और इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं को हर नागरिक तक पहुँचाना।
2. सरकारी सेवाओं का सहज और पारदर्शी वितरण – ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और वित्तीय योजनाएँ सीधे लाभार्थी तक पहुँचें।
3. नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण – जिससे ग्रामीण समुदाय ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का सक्रिय हिस्सा बन सके।

डिजिटल इंडिया की महत्ता को समझने के लिए ग्रामीण समाज की जटिलताओं को देखना आवश्यक है। ग्रामीण भारत में जातीय और लैंगिक असमानताएँ, सीमित अवसंरचना, और कम आय के कारण तकनीकी अपनाने की रफ्तार धीमी रही है। इसके बावजूद स्मार्टफोन की गिरती कीमतें, मोबाइल टेलीफोनी का तीव्र प्रसार और सस्ती डेटा सेवाएँ एक नई आशा लेकर आई हैं। डिजिटल इंडिया ने इन्हीं सकारात्मक रुझानों को नीति समर्थन

और संस्थागत ढाँचे के साथ जोड़ा। भारतनेट जैसी परियोजनाओं ने गाँवों में ब्रॉडबैंड पहुँचाने का बीड़ा उठाया, जबकि कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSC) ने नागरिक सेवाओं को नजदीकी स्तर तक पहुँचाया। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA) ने लाखों लोगों को बुनियादी कंप्यूटर और इंटरनेट कौशल प्रदान किए। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का महत्व केवल तकनीकी नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का भी प्रतीक है। यह ग्रामीण भारत को वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की प्रमुख पहलें

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कई परस्पर जुड़े उपक्रमों का समुच्चय है, जिनका उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों को इंटरनेट आधारित सेवाएँ, डिजिटल पहचान और इलेक्ट्रॉनिक शासन की सुविधाएँ प्रदान करना है। नीचे प्रमुख पहलें विस्तार से दी जा रही हैं:

भारतनेट परियोजना

भारतनेट, जिसे पहले नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (NOFN) कहा जाता था, डिजिटल इंडिया का सबसे बुनियादी अवयव है। इसका लक्ष्य है 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड से जोड़ना।

पृष्ठभूमि: 2011 में शुरू और 2015 में डिजिटल इंडिया के तहत पुनर्गठित।

कार्यान्वयन: चरणबद्ध योजना - पहले चरण में 1 लाख ग्राम पंचायत, दूसरे चरण में शेष 1.5 लाख।

प्रगति: 2023 तक लगभग 1.9 लाख पंचायतों में फाइबर कनेक्शन स्थापित किए जा चुके हैं।

ग्रामीण प्रभाव: स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों, कृषि मंडियों और पंचायत भवनों में हाई-स्पीड इंटरनेट उपलब्ध हुआ, जिससे ई-गवर्नेंस, ई-लर्निंग और टेलीमेडिसिन को आधार मिला।

तालिका-1: भारत नेट की प्रगति

वर्ष	**जुड़ी हुई ग्राम पंचायतें**
2015	35,000
2018	1,20,000
2020	1,50,000
2023	1,90,000

तालिका-2: ग्रामीण इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की वृद्धि (2014-2023)

वर्ष	**ग्रामीण इंटरनेट उपयोगकर्ता**
2014	6 करोड़
2018	15 करोड़
2020	22 करोड़
2023	30 करोड़

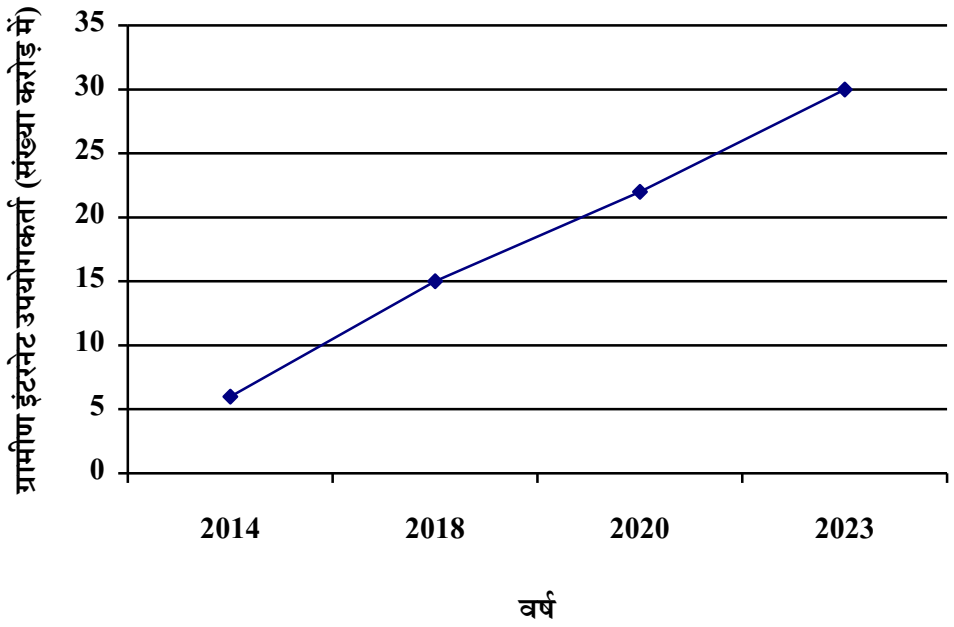

कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSC)

CSC ग्रामीण नागरिकों के लिए "डिजिटल दरवाज़ा" हैं।

भूमिका: जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन, बिजली बिल, आधार सेवाएँ, बीमा और बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान करना।

रोज़गार सृजन: लाखों ग्रामीण युवाओं को Village Level Entrepreneur (VLE) के रूप में काम करने का अवसर।

लाभ: दूरस्थ गाँवों में सरकारी कार्यालय जाने की आवश्यकता कम, सेवाएँ स्थानीय स्तर पर।

उदाहरण: बिहार के मधुबनी जिले में CSC के माध्यम से किसानों को फसल बीमा योजनाओं में त्वरित नामांकन की सुविधा मिली।

प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA)

डिजिटल इंडिया की सफलता नागरिकों की डिजिटल समझ पर निर्भर करती है।

उद्देश्य: 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल साक्षर बनाना।

प्रशिक्षण सामग्री: कंप्यूटर का मूल उपयोग, ई-मेल, ऑनलाइन भुगतान, इंटरनेट सुरक्षा।

महिला सहभागिता: अभियान में महिलाओं को विशेष रूप से शामिल किया गया, जिससे महिला उद्यमिता को बल मिला।

प्रभाव: अब ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग, ऑनलाइन शिक्षा और सरकारी योजनाओं का उपयोग अधिक लोग कर पा रहे हैं।

डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नकदी पर निर्भरता लंबे समय से रही है।

BHIM और UPI: आसान और त्वरित लेन-देन, जो स्मार्टफोन पर QR कोड से संभव।

आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS): केवल आधार और अंगूठे की मदद से बैंकिंग सुविधा।

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT): पेंशन, छात्रवृत्ति और सब्सिडी सीधे बैंक खातों में।

प्रभाव: बिचौलियों की भूमिका कम, पारदर्शिता और समय की बचत।

ई-गवर्नेंस और मोबाइल एप्स

डिजिटल इंडिया ने शासन को "पेपरलेस और फेसलेस" बनाने पर जोर दिया।

UMANG: एक ही ऐप पर 200 से अधिक सरकारी सेवाएँ।

DigiLocker: शैक्षणिक प्रमाण पत्र और दस्तावेजों का सुरक्षित डिजिटल भंडारण।

e-NAM: किसानों के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार।

Aarogya Setu और CoWIN: महामारी के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं का डिजिटल समाधान।

प्रभाव: ग्रामीण नागरिकों को सरकारी दफ्तरों में बार-बार चक्कर लगाने से मुक्ति।

शिक्षा और ई-लर्निंग पहलें

SWAYAM और DIKSHA प्लेटफॉर्म: ग्रामीण छात्रों को गुणवत्तापूर्ण ऑनलाइन पाठ्यक्रम।

स्मार्ट क्लासरूम: राज्य सरकारों के सहयोग से कई गाँवों में स्मार्ट बोर्ड और ई-कंटेंट।

लाभ: दूरदराज़ के छात्र उच्च शिक्षा संसाधनों तक पहुँच पा रहे हैं।

स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल कार्यक्रम

e-Hospital और Telemedicine: ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों को विशेषज्ञ डॉक्टरों से जोड़ना।

जनऔषधि केंद्र ऑनलाइन सेवाएँ: दवाओं की उपलब्धता और मूल्य जानकारी।

फायदा: गर्भवती महिलाओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग, टीकाकरण ट्रैकिंग।

कृषि और ग्रामीण विकास

mKisan पोर्टल: मौसम, बीज, खाद और बाजार मूल्य की जानकारी SMS/ऐप द्वारा।

फसल बीमा ऐप: फसल बीमा दावे का ऑनलाइन पंजीकरण।

परिणाम: किसान समय पर निर्णय लेकर उत्पादन और आय बढ़ा सकते हैं।

इन सभी पहलों ने मिलकर ग्रामीण भारत को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा है। आज कई गाँवों में लोग न केवल सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, बल्कि ई-कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन शिक्षा में भी भागीदारी कर रहे हैं। इससे न केवल समय और लागत की बचत हुई है, बल्कि सामाजिक पारदर्शिता और आर्थिक सशक्तिकरण भी बढ़ा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभाव

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने ग्रामीण भारत में सामाजिक और आर्थिक जीवन के कई आयामों को छुआ है। यह प्रभाव केवल तकनीकी सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार और वित्तीय समावेशन सहित ग्रामीण समाज की संरचना और सोच पर भी गहरा असर डालता है।

शिक्षा में परिवर्तन

ग्रामीण भारत में लंबे समय तक शिक्षा अवसंरचना की कमी रही। कई गाँवों में स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक और गुणवत्तापूर्ण पाठ्य सामग्री का अभाव था। डिजिटल इंडिया ने इस परिदृश्य को बदला।

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म: SWAYAM, DIKSHA और ई-पाठशाला ने छात्रों को उच्च गुणवत्ता के डिजिटल कोर्स उपलब्ध कराए।

स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल लाइब्रेरी: उत्तर प्रदेश, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में हजारों स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड और ई-कंटेंट उपलब्ध कराया गया।

महिला शिक्षा में प्रगति: ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियाँ अब घर बैठे ऑनलाइन कोर्स कर पा रही हैं, जिससे उच्च शिक्षा की राह आसान हुई।

COVID-19 के दौरान: ऑनलाइन कक्षाओं ने महामारी में शिक्षा को जारी रखा और डिजिटल संसाधनों की आवश्यकता को रेखांकित किया।

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार

स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच ग्रामीण क्षेत्रों में हमेशा चुनौतीपूर्ण रही है। डिजिटल पहल ने इस खाई को काफी हद तक पाटा।

टेलीमेडिसिन: ई-संजीवनी जैसे प्लेटफॉर्म ने गाँव के मरीजों को विशेषज्ञ डॉक्टरों से वीडियो कॉल पर परामर्श का अवसर दिया।

e-Hospital सेवाएँ: मरीज अब ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और मेडिकल रिकॉर्ड डिजिटल रूप में सुरक्षित रख सकते हैं।

जन औषधि सूचना: दवाओं की कीमत और उपलब्धता की जानकारी मोबाइल ऐप से मिलती है।

टीकाकरण और मातृ स्वास्थ्य: CoWIN और स्वास्थ्य ट्रैकिंग एप्स ने गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण को व्यवस्थित बनाया।

कृषि में नवाचार और बाजार तक पहुँच

कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। डिजिटल इंडिया ने किसानों को नए साधन दिए:

e-NAM (राष्ट्रीय कृषि बाजार): किसानों को अपनी उपज के लिए पूरे देश में बेहतर दाम पाने का अवसर।

mKisan पोर्टल और SMS अलर्ट: मौसम, मिट्टी परीक्षण और फसल रोग संबंधी जानकारी समय पर प्राप्त होती है।

डिजिटल भुगतान: किसान सीधे बैंक खाते में फसल बिक्री का भुगतान पाते हैं, जिससे बिचौलियों की भूमिका कम होती है।

ड्रोन और GIS तकनीक: कुछ राज्यों में फसल निगरानी और उर्वरक छिड़काव के लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग बढ़ा है।

रोजगार और उद्यमिता के अवसर

ग्रामीण युवाओं को रोजगार देना हमेशा कठिन चुनौती रही है।

कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSC): लाखों युवाओं ने VLE (Village Level Entrepreneur) के रूप में रोजगार पाया।

डिजिटल उद्यमिता: महिलाएँ और स्वयं सहायता समूह अब ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर हस्तशिल्प और कृषि उत्पाद बेच रहे हैं।

फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन कार्य: इंटरनेट की उपलब्धता से ग्रामीण युवा आईटी आधारित सेवाएँ, डिज़ाइन, कंटेंट राइटिंग और ऑनलाइन ट्यूशन जैसे कार्य कर रहे हैं।

स्टार्टअप संस्कृति: कुछ क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना ने ग्रामीण स्टार्टअप को प्रोत्साहन दिया है, जैसे ग्रामीण पर्यटन और जैविक खेती से जुड़े ऑनलाइन पोर्टल।

वित्तीय समावेशन और पारदर्शिता

वित्तीय सेवाओं तक पहुँच ग्रामीण समाज के लिए बड़ा बदलाव है।

जन धन योजना और आधार: बैंक खाते खोलने और आधार-आधारित लेन-देन की सुविधा ने लाखों ग्रामीणों को औपचारिक बैंकिंग से जोड़ा।

UPI और BHIM ऐप: अब छोटे दुकानदार भी QR कोड से भुगतान स्वीकार कर सकते हैं।

DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर): पेंशन, छात्रवृत्ति और कृषि सब्सिडी सीधे लाभार्थियों तक पहुँचती है, जिससे भ्रष्टाचार घटा है।

माइक्रोफाइनेंस और बीमा: डिजिटल प्लेटफॉर्म से ग्रामीण महिलाओं को सूक्ष्म ऋण और बीमा योजनाएँ आसानी से मिल रही हैं।

सामाजिक-सांस्कृतिक बदलाव

डिजिटल कनेक्टिविटी ने सामाजिक दृष्टिकोण भी बदला है।

सूचना तक समान पहुँच: महिलाएँ और युवतियाँ अब समाचार, सरकारी योजनाओं और शिक्षा सामग्री तक सीधे पहुँच पा रही हैं।

सामुदायिक भागीदारी: पंचायत बैठकें और सरकारी योजनाओं पर जानकारी अब ऑनलाइन साझा होती है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी।

प्रवासी मजदूरों के लिए सहूलियत: ग्रामीण लोग शहरों में काम करने वाले अपने परिजनों से वीडियो कॉल और ऑनलाइन मनी ट्रांसफर के माध्यम से जुड़े रहते हैं।

सांस्कृतिक आदान-प्रदान: इंटरनेट ने ग्रामीण कलाकारों और लोकसंगीतकारों को बड़े मंच तक पहुँचाया है।

महिलाओं और हाशिए पर समुदायों पर प्रभाव

महिला सशक्तिकरण डिजिटल इंडिया की बड़ी उपलब्धि है। महिलाएँ अब ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल मार्केटिंग सीख रही हैं। स्वयं सहायता समूह ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने उत्पाद बेच रहे हैं। अनुसूचित जाति और जनजातीय समुदायों के युवा आईटी प्रशिक्षण से नए अवसर पा रहे हैं।

डिजिटल इंडिया ने ग्रामीण जीवन की संरचना को बदलने में अहम भूमिका निभाई है। शिक्षा से लेकर कृषि और वित्तीय सेवाओं तक हर क्षेत्र में डिजिटल तकनीक ने पहुँच बढ़ाई है। हालाँकि, यह परिवर्तन समान रूप से सभी गाँवों में नहीं हुआ। जिन क्षेत्रों में बिजली, नेटवर्क और डिजिटल साक्षरता की कमी है, वहाँ प्रगति धीमी है। फिर भी, यह पहल ग्रामीण भारत को ज्ञान आधारित और आत्मनिर्भर समाज की ओर ले जाने में मील का पत्थर सिद्ध हो रही है।

चुनौतियाँ

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने ग्रामीण भारत में नई संभावनाएँ खोली हैं, परंतु इसकी सफलता कई गंभीर चुनौतियों से प्रभावित होती है। ये चुनौतियाँ केवल तकनीकी अवसंरचना तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और नीतिगत पहलुओं से भी जुड़ी हैं।

डिजिटल अवसंरचना की कमी

कनेक्टिविटी का असमान वितरण: पहाड़ी और दूरस्थ इलाकों में अब भी हाई-स्पीड इंटरनेट उपलब्ध नहीं है। उदाहरण के लिए, पूर्वोत्तर भारत और जम्मू-कश्मीर के कई गाँवों में 4G कवरेज सीमित है।

बिजली आपूर्ति: लगातार बिजली कटौती और कम वोल्टेज के कारण इंटरनेट सेवाएँ स्थिर नहीं रहतीं।

रखरखाव और तकनीकी सहयोग: भारतनेट जैसी परियोजनाओं में ऑप्टिकल फाइबर के रखरखाव और समय पर मरम्मत के लिए प्रशिक्षित कर्मियों की कमी है।

डिजिटल साक्षरता का अभाव

जनजागरण की कमी: कई ग्रामीण नागरिकों के पास स्मार्टफोन होने पर भी वे ई-गवर्नेंस, डिजिटल भुगतान या ऑनलाइन शिक्षा का सही उपयोग नहीं कर पाते।

महिलाओं और बुजुर्गों की भागीदारी: सामाजिक मान्यताओं और तकनीक का डर इन्हें डिजिटल सेवाओं से दूर रखता है।

भाषाई बाधा: कई डिजिटल प्लेटफॉर्म हिंदी या स्थानीय भाषाओं में पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं हैं, जिससे सीमित अंग्रेज़ी ज्ञान वाले लोग वंचित रह जाते हैं।

आर्थिक सीमाएँ

स्मार्टफोन और डेटा की लागत: हालांकि डेटा सस्ता हुआ है, परंतु आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए स्मार्टफोन और नियमित रिचार्ज अभी भी बोझ हैं।

डिवाइस की गुणवत्ता: कम कीमत वाले स्मार्टफोन की कम स्टोरेज और कमजोर बैटरी डिजिटल शिक्षा और टेलीमेडिसिन के उपयोग में बाधा डालती है।

साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता

साइबर अपराध का खतरा: फिशिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी और पहचान चोरी के मामले ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं।

जागरूकता की कमी: कई लोग OTP साझा कर लेते हैं या संदिग्ध लिंक पर क्लिक कर देते हैं।

डेटा संरक्षण कानून की चुनौतियाँ: ग्रामीण नागरिक अक्सर यह नहीं जानते कि उनका निजी डेटा कैसे सुरक्षित रखा जाए।

सामाजिक असमानताएँ

जातीय और लैंगिक भेदभाव: कई गाँवों में महिलाओं को स्मार्टफोन रखने से रोका जाता है या इंटरनेट उपयोग पर पाबंदी होती है।

आर्थिक विभाजन: सम्पन्न किसान और व्यापारी तकनीक का जल्दी लाभ उठाते हैं, जबकि छोटे किसान और मजदूर पीछे रह जाते हैं।

शिक्षा का स्तर: कम साक्षरता वाले लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म के जटिल इंटरफेस से डरते हैं।

नीतिगत और प्रशासनिक बाधाएँ

विभागीय समन्वय की कमी: कई बार केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं में तालमेल की कमी से परियोजनाएँ विलंबित होती हैं।

फंडिंग में देरी: भारतनेट जैसे बड़े प्रोजेक्ट समय पर फंड न मिलने से पीछे रह जाते हैं।

स्थानीय भागीदारी का अभाव: पंचायत स्तर पर तकनीकी निर्णयों में समुदाय की राय कम शामिल होती है।

सांस्कृतिक और व्यवहारिक चुनौतियाँ

तकनीक पर अविश्वास: कुछ ग्रामीण समाज में यह धारणा है कि डिजिटल भुगतान असुरक्षित है या सरकारी ऐप डेटा का गलत उपयोग करेंगे।

आदतों में बदलाव की धीमी गति: नकद लेन-देन और पारंपरिक तरीकों की आदतें जल्दी नहीं बदलतीं।

पर्यावरणीय और भौगोलिक बाधाएँ

भूगोल और मौसम: पहाड़ी, रेगिस्तानी और तटीय क्षेत्रों में नेटवर्क टावर स्थापित करना कठिन और महंगा है।

प्राकृतिक आपदाएँ: बाढ़ और चक्रवात से नेटवर्क अवसंरचना को बार-बार नुकसान होता है।

इन चुनौतियों के कारण डिजिटल इंडिया की प्रगति गाँव-गाँव में समान नहीं है। कई स्थानों पर डिजिटल सेवाएँ उपलब्ध होने के बावजूद उनका उपयोग सीमित है। समाधान के लिए बहुस्तरीय रणनीति आवश्यक है- अवसंरचना निवेश, स्थानीय भाषाओं में सामग्री, व्यापक डिजिटल साक्षरता अभियान और साइबर सुरक्षा पर जागरूकता।

निष्कर्ष और सुझाव

निष्कर्ष

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने ग्रामीण भारत के विकास को एक नई दिशा दी है। पिछले वर्षों में हुए परिवर्तन से यह स्पष्ट है कि डिजिटल प्रौद्योगिकी केवल सूचना तक पहुँच का साधन नहीं रही, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव का प्रमुख आधार बन गई है।

आर्थिक दृष्टि से: किसानों को e-NAM जैसे प्लेटफार्मों से बेहतर बाजार मिला, छोटे दुकानदारों और स्वयं सहायता समूहों ने डिजिटल भुगतान से कारोबार बढ़ाया।

सामाजिक दृष्टि से: शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ अब पहले से अधिक सुलभ हैं। टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन शिक्षा ने ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सीधा सुधार किया।

सांस्कृतिक दृष्टि से: महिलाओं और युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा, और उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रतिभा और व्यवसाय को स्थान दिलाया।

हालाँकि, यह परिवर्तन समान रूप से सभी क्षेत्रों तक नहीं पहुँचा। कमजोर डिजिटल अवसंरचना, सीमित साक्षरता, सामाजिक असमानता और साइबर सुरक्षा की समस्याएँ अब भी बड़ी बाधा हैं। यदि इन चुनौतियों को समय पर संबोधित न किया गया तो डिजिटल इंडिया की गति धीमी पड़ सकती है।

प्रमुख उपलब्धियाँ

डिजिटल अवसंरचना का विस्तार: भारतनेट और मोबाइल नेटवर्क विस्तार ने लाखों गाँवों को इंटरनेट से जोड़ा।

ई-गवर्नेंस में पारदर्शिता: DBT ने योजनाओं का लाभ सीधे नागरिकों तक पहुँचाया, भ्रष्टाचार कम हुआ।

वित्तीय समावेशन: जन धन योजना और UPI ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नकदी पर निर्भरता से मुक्त किया।

शिक्षा और स्वास्थ्य में पहुँच: DIKSHA और ई-संजीवनी जैसे प्लेटफॉर्म ने गुणवत्ता और पहुँच दोनों को मजबूत किया।

महिला सशक्तिकरण: स्वयं सहायता समूहों और महिला VLE ने गाँवों में रोजगार और नेतृत्व के नए अवसर बनाए।

प्रमुख चुनौतियाँ

1. इंटरनेट कनेक्टिविटी की असमानता
2. डिजिटल साक्षरता का अभाव
3. साइबर अपराध और डेटा गोपनीयता
4. भाषाई विविधता और सामग्री का अभाव
5. आर्थिक विषमता और लैंगिक भेदभाव
6. इन चुनौतियों का समाधान बिना दीर्घकालिक रणनीति और समन्वित प्रयास के संभव नहीं है।

सुझाव

डिजिटल अवसंरचना में निरंतर निवेश

1. दूरदराज़ और पहाड़ी क्षेत्रों में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट और 5G सेवाओं को प्राथमिकता दी जाए।
2. बिजली आपूर्ति को स्थिर और किफायती बनाने के लिए सौर ऊर्जा जैसी वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग बढ़ाया जाए।

व्यापक डिजिटल साक्षरता अभियान

1. पंचायत स्तर पर नियमित प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएँ।

2. महिलाओं और बुजुर्गों के लिए विशेष मॉड्यूल तैयार हों, ताकि वे बिना झिझक डिजिटल सेवाओं का उपयोग कर सकें।

स्थानीय भाषाओं में सामग्री और ऐप विकास

1. सभी सरकारी पोर्टल और मोबाइल ऐप हिंदी के साथ-साथ प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध हों।
2. स्थानीय शिक्षकों और उद्यमियों को डिजिटल सामग्री बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता

1. गाँव स्तर पर साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए जाएँ।
2. सुरक्षित भुगतान प्रणालियों और डेटा संरक्षण कानून को सख्ती से लागू किया जाए।

महिला और हाशिए पर समुदायों के लिए विशेष नीतियाँ

1. महिला स्वयं सहायता समूहों को सस्ती दर पर स्मार्टफोन और इंटरनेट पैकेज उपलब्ध कराए जाएँ।
2. अनुसूचित जाति और जनजातीय युवाओं के लिए डिजिटल स्टार्टअप इनक्यूबेशन केंद्र स्थापित हों।

स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा

1. ग्रामीण स्टार्टअप को कर छूट और कम ब्याज ऋण दिया जाए।
2. कृषि-आधारित ई-कॉमर्स और ग्रामीण पर्यटन जैसे क्षेत्रों में निजी निवेश आकर्षित किया जाए।

निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली

1. डिजिटल इंडिया की सभी परियोजनाओं के लिए पारदर्शी मूल्यांकन तंत्र विकसित किया जाए।
2. ग्राम सभा और नागरिक समाज को फीडबैक प्रक्रिया में शामिल किया जाए।

भविष्य की दिशा

डिजिटल इंडिया का अगला चरण केवल सेवाओं की उपलब्धता तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि डिजिटल सशक्तिकरण से डिजिटल नेतृत्व की ओर

बढ़ना चाहिए। इसका अर्थ है कि ग्रामीण समुदाय केवल उपभोक्ता न रहें, बल्कि कंटेंट निर्माण, ऐप विकास और डिजिटल स्टार्टअप के निर्माता बनें। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन और डेटा एनालिटिक्स जैसी उभरती तकनीकें जब गाँवों तक पहुँचेंगी, तब वास्तविक डिजिटल क्रांति संभव होगी।

डिजिटल इंडिया ने साबित किया है कि यदि सही नीतिगत दिशा और तकनीकी निवेश मिलें तो ग्रामीण भारत वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था का सक्रिय हिस्सा बन सकता है। यह कार्यक्रम केवल सरकार की योजना नहीं, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन है, जिसमें प्रत्येक नागरिक की भागीदारी अनिवार्य है। आने वाले वर्षों में यदि सुझाए गए कदम लागू किए जाएँ तो यह पहल न सिर्फ़ ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता को नई ऊँचाई पर ले जाएगी, बल्कि भारत को विश्व स्तर पर डिजिटल शक्ति के रूप में स्थापित करेगी।

सन्दर्भ:

भारत सरकार. (2023). *डिजिटल इंडिया प्रगति रिपोर्ट 2022–23*. नई दिल्ली: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय.https://www.digitalindia.gov.in

भारत सरकार. (2022). *भारतनेट परियोजना वार्षिक रिपोर्ट 2021–22*. नई दिल्ली: दूरसंचार विभाग.

नीति आयोग. (2021). *ग्रामीण भारत में डिजिटल परिवर्तन पर विशेष अध्ययन*. नई दिल्ली: नीति आयोग प्रकाशन.

विश्व बैंक. (2020). *भारत में डिजिटल समावेशन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था*. वाशिंगटन, डी.सी.: विश्व बैंक प्रकाशन.https://www.worldbank.org

इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI). (2022). *भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ता रिपोर्ट 2022*. नई दिल्ली: IAMAI रिसर्च.

भारतीय रिज़र्व बैंक. (2023). डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन पर वार्षिक रिपोर्ट 2022–23. मुंबई: आरबीआई.

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO). (2022). *ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और डिजिटल साक्षरता सर्वेक्षण 2021–22*. नई दिल्ली: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय.

कुमार, आर., & मिश्रा, एस. (2021). ग्रामीण भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव. *भारतीय ग्रामीण विकास पत्रिका*, 47(3), 15–28.

शर्मा, पी. (2020). टेलीमेडिसिन और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा: डिजिटल इंडिया का योगदान. *जन स्वास्थ्य समीक्षा*, 12(2), 44–56.

Copyright © 2025 Siri Research Foundation. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY-NC-ND 4.0).